राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष – 03 | अंक – 351 | जौनपुर | सोमवार, 11 अगस्त 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

कुछ लोगों को कोसी में बिहार चुनाव दिखेगा : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य सांसदों के लिए पर्याप्त आवास की तीव्र कमी को दूर करना और ऊर्ध्वाधर आवास प्रारूप में आधुनिक, पर्यावरण–अनुकूल आवास प्रदान करना है। उद्घाटन के एक भाग के रूप में, प्रधानमंत्री ने परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया, निर्माण कार्य में शामिल श्रमजीवियों से बातचीत की और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कर्तव्य पथ ओर सामान्य केंद्रीय सचिवालय यानी कर्तव्य भवन का

लोकार्पण किया था। आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रिहायशी कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि इन 4 टावर्स के नाम भी बहुत सुंदर हैं। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, भारत की चार महान नदियां, जो करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। अब उनकी प्रेरणा से हमारे जन प्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। विपक्ष पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी पर नाम रखा है, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। ऐसे छोटे मन के लोगों के मन की परेशानियां भी दिखेंगी। नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद साथी जिस नए आवास में प्रवेश करेंगे, अभी मुझे उसका एक नमूना फ्लैट देखने का भी मौका मिला। मुझे पुराने सांसद आवासों को देखने का मौका भी मिलता रहा है। पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उनसे मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे, तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे।

विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर योगी का तंज

लखनऊ, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा और लोकतंत्र एक ही नदी के दो अलग–अलग छोर हैं। सदन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र एक ही नदी के दो अलग–अलग छोर हैं। उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा कब से होने लगा? लोकतंत्र की बात करना उन्हें शोभा नहीं देता। संभल में उन्होंने क्या किया, यह सबको पता है। राज्य भर के उदाहरणों का हवाला देते हुए योगी ने कहा कि चाहे संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, सपा के कुकर्मों के बारे में सबको पता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। अगर एनडीए सरकार विकास करना चाहती है, तो आपको (समाजवादी पार्टी को) बुरा लग रहा है। हम पूरे प्रदेश के व्यापारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सपा शासन में व्यापारियों पर गुंडा टैक्स लगाया जाता था। अपनी आलोचना जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि

इसी वजह से व्यापारी आपसे नाराज हैं और समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा बार–बार भुगतना पड़ रहा है। व्यापारियों के विकास के लिए कदम उठाने के बजाय, उन्होंने (समाजवादी पार्टी ने) उनकी राह में रोड़े ही अटकाए हैं। समाजवादी पार्टी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छे विकास का समर्थन करेंगे। सीएम योगी ने सत्र शुरू होने से पहले यूपी विधानसभा को 24 घंटे चलाने संबंधी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी की आलोचना की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सरकार और भाजपा की विकास के प्रति प्रतिबद्धता है। विकास उनके एजेंडे में नहीं है। जब हमने सतत विकास लक्ष्यों, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, कृषि विकास, कौशल विकास, रोजगार से जुड़े मुद्दों पर 36 घंटे सदन चलाया, तब भी समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विकास उनके एजेंडे में नहीं है। मीडिया से बात करते हुए।

अखिलेश यादव ने यूपी में वोट लूट का आरोप लगाया

लखनऊ, (एजेंसी)। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर दो वोटर आईडी रखने के आरोप के बाद, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष

अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा है। अखिलेश ने योगी पर श्वोट लूटश् और श्बूथ लूटश् में मदद करने का आरोप लगाया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास दो अलग–अलग निर्वाचन क्षेत्रों के दो वोटर आईडी नंबर हैं। इस आरोप का जवाब देते हुए सिन्हा ने इन दावों को खारिज कर दिया है। इस विवाद को उत्तर प्रदेश से जोडते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बिहार के उपमुख्यमंत्री के पास दो वोटर आईडी हैं, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्वोट लूटश् में मदद कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल नवंबर में हुए उपचुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इसके अलावा, उन्होंने मीरापुर में कमिश्नर, एसएसपी और डीएम पर यह सुनिश्चित करने के लिए बल का उपयोग करने का आरोप लगाया कि लोग वोट डालने के लिए बाहर न निकलें। एक वीडियो में, अखिलेश यादव ने मीरापुर में एक पुलिसकर्मी द्वारा महिला मतदाताओं पर बंदूक तानने की कथित घटना का भी उल्लेख किया।

विपक्ष के हंगामें के बीच कई बिल पास, लोकसभा ने आयकर विधेयक को दी मंजूरी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मानसून सत्र के 16वें दिन भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हालांकि, आज हंगामे के बीच ही लोकसभा और राज्यसभा में कई विधेयक पारित किए गए। बावजूद इसके विपक्षी सांसदों का शोर शराबा जारी रहा जिसके कारण दोनों सदनों के कार्यवाही को स्थागित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी कई। वहीं, राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। राज्यसभा में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य दलों के सदस्यों ने मणिपुर में शांति एवं स्थिरता कायम करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य में आतंरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों

का पुनर्वास किया जाना चाहिए, वहीं बीजद ने राज्य को वित्तीय पैकेज देने की मांग की। राज्यसभा में सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच तीन विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दिए जाने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने विरोध जताते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। वहीं सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा जरूर होनी चाहिए लेकिन सदन को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। लोकसभा ने सोमवार को आयकर संबंधी उस नए विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी, जो आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे पर विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 लोकसभा में पारित करने के लिए पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से अनुमोदित किया। इस विधेयक में प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। लोकसभा ने कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य एकीकृत पेंशन योजना के अंशधारकों को कर छूट प्रदान करना है। संसद ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लिए सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले एक अहम विधेयक को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी।

आवारा कुत्तों से परेशान हैं लोग, चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे सुप्रीम कोर्ट का आदेश : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार शीघ्र ही एक नीति लेकर आएगी तथा योजनाबद्ध तरीके से उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को दिल्ली–एनसीआर के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया और कहा कि ये कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं आएंगे। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के मामले में 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू किए गए एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को ष्बेहद गंभीरष् बताते हुए, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कई निर्देश जारी किए और किसी व्यक्ति या संगठन के काम में बाधा डालने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसके चलते अदालत अवमानना की कार्यवाही भी शुरू कर सकती है। गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ष्दिल्ली के लोग आवारा कुत्तों से तंग आ चुके हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों को राहत पहुँचाना चाहते हैं। आवारा कुत्तों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। हम एक नीति बनाकर लोगों को राहत पहुँचाएँगे। दिल्ली सरकार ने भी इस मुद्दे पर कई बैठकें की हैं। पिछले हफ्ते मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा था कि सरकार एक मानवीय नीति लेकर आएगी। कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटने के लिए कई निर्देश पारित करते हुए न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने में अधिकारियों के काम में बाधा डालेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र को प्रदेश व जनहित में उपयोगी बनाना जरूरी – मायावती

लखनऊ, (एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को प्रदेश व जनहित में उपयोगी बनाना जरूरी है। मायावती ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, संक्षिप्त होने के बावजूद केवल औपचारिकता पूर्ति वाला नहीं हो, बल्कि इसको सही से प्रदेश व जनहित में उपयोगी बनाना जरूरी है, जिसके लिए सरकार एवं विपक्ष दोनों को अपने–अपने राजनीतिक स्वार्थ, द्वेष व कटूता आदि को त्याग कर आगे बढ़ना होगा।'' उन्होंने कहा, ''इसके अलावा, संसद का जो अभी मानसून सत्र चल रहा है उसके भी पूरी तरह शान्तिपूर्ण तरीके से नहीं चलने से वह जन अपेक्षा के अनुसार सही से कार्य नहीं कर पा रहा है। इस कारण जनता व देश के ज्वलंत मुद्दों पर पूरी गंभीरता से चर्चा नहीं हो पाने से लोगों में

चिन्ता स्वाभाविक है।'' उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''वैसे भी भारतीय व्यापार पर भारी अमेरिकी 'टैरिफ' के कारण देश की अर्थव्यवस्था व विकास पर जो बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है उसकी चर्चा व्यापक रूप से हर जगह गर्म है, जिसपर खास तौर से संसद में सही से चिन्तन–मनन करने की जरूरत है, क्योंकि यह देश के 'अच्छे दिन' से जुड़ा देशहित का खास मुद्दा है'' उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हल्के में लेकर देश के भविष्य को दाव पर नहीं लगाया जा सकता है और सरकार व विपक्ष दोनों इस पर उचित व समुचित ध्यान दें। बसपा नेता ने कहा, ''साथ ही, चाहे वोटर व वोटर सूची तथा उसके पुरीक्षण एवं ईवीएम आदि से संबंधित देश, जनहित एवं लोकतंत्र से जुड़े मामलों में जो किस्म–किस्म की बातें देश में हो रही हैं उन संदेहों को अवश्य ही यथाशीघ्र दूर किया जाए तो यह बेहतर होगा।'' उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है।

अब हम देश और संसद का समय और बर्बाद नहीं होने देंगे : किरेन रिजिजू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर चालू सत्र में समय बर्बाद करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार आज संसद के दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराएगी। उन्होंने कहा, ष्बस, बहुत हो गया।ष् उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने बहुत समय बर्बाद किया है। अब हम देश और संसद का समय और बर्बाद नहीं होने देंगे। सरकार महत्वपूर्ण विधेयक पारित करना चाहती है। आज हम लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में महत्वपूर्ण विधेयक पारित करेंगे। एक व्यक्ति की मूर्खता और एक परिवार की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता। किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि कई विपक्षी सांसदों ने भी आकर कहा कि वे लाचार हैं। उनके नेता उन्हें जबरदस्ती हंगामा करने के लिए कहते हैं। हम रोज एक मुद्दे पर देश और संसद का समय बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए हम महत्वपूर्ण विधेयक पारित करेंगे। उन्होंने कहा कि आज भी उन्होंने (विपक्ष ने) चुनाव आयोग जाने के लिए समय माँगा और चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी (ष्छक्) गठबंधन को हर पार्टी से दो–दो सदस्य भेजने को कहा। तीस सदस्यों को बुलाया गया, लेकिन वे नहीं गए।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में, वे उन 30 लोगों को तय नहीं कर पाए... अब खड़गे जी कह रहे हैं कि सभी विपक्षी सदस्य टप्छ हैं, तो क्या 150 लोग चुनाव आयुक्त के कमरे में घुस जाएँगे? इंडिया (ष्छक्) गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, उन्हें संसद पर भरोसा नहीं है। वे हमारे देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। हम विपक्ष से आखिरी अपील करते हैं। हम बिल पास करेंगे। आपको चर्चा में भाग लेना चाहिए। रिजिजू ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते। एक पार्टी, एक परिवार या एक व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह संवैधानिक नहीं हो सकता। लोकतंत्र में, वे लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी से हैं... इन लोगों को लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है।

अंग प्रतिरोपण नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि अंग प्रतिरोपण की प्रतीक्षा सूची में महिला मरीजों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, ताकि लैंगिक असमानता को दूर किया जा सके। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि अंग प्रतिरोपण की प्रतीक्षा कर रहे मृत दाताओं के करीबी रिश्तेदारों और संबंधियों को प्राथमिकता दी जाए। ये सुझाव स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रतिरोपण संगठन (नोओटीटीओ) की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी परामर्श में दिए गए हैं। यह परामर्श दो अगस्त को 15वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर अंगदान और प्रतिरोपण को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया था। इस परामर्श

में कहा गया है कि मृत अंगदाताओं का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए और उनके परिजनों को 15 अगस्त, 26 जनवरी, राज्य स्थापना दिवस आदि अवसरों पर राज्य/जिला स्तर के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाए। इसमें आगे कहा गया है, श्मृत दाता अंग प्रतिरोपण की प्रतीक्षा सूची में महिला मरीजों को अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया जाए। ताकि लैंगिक असमानता को दूर किया जा सके। यदि किसी मृत दाता के निकट संबंधी को अंग प्रतिरोपण की जरुरत है, तो उसे प्राथमिकता दी जाए। इसमें सभी ट्रॉमा सेंटर में अंग और ऊतक निकालने की सुविधाएं विकसित करने और उन्हें अंग एवं ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम (थोटा), 1994 के तहत अंग निकासी केंद्र के रूप में पंजीकृत करने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह, राज्यों को चरणबद्ध तरीके से अपने–अपने मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने की सलाह दी गई है। राज्यों से कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार और मस्तिष्काघात के मरीजों में संभावित मृत दाताओं की समय पर पहचान के लिए आपातकालीन सेवाकर्मियों और एंबुलेंस कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए। तथा इस बारे में अस्पताल के अंगदान समन्वयक को सूचित किया जाए। इस परामर्श में राज्यों से एक ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने का सुझाव भी दिया गया है।

संक्षिप्त खबरें

अब तक किसी भी पार्टी ने मतदाता सूची पर दर्ज नहीं कराई आपत्ति

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनावी राज्य बिहार में संशोधित मसौदा मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में राजनीतिक दलों ने अभी तक कोई आपत्ति या दावा दर्ज नहीं कराया है, क्योंकि सोमवार सुबह 11 बजे तक ऐसा कोई दावा नहीं आया है। आज अपना दैनिक बुलेटिन जारी करते हुए, चुनाव आयोग ने कहा कि 1 अगस्त से 11 अगस्त तक, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के 1,60,813 से अधिक बूथ स्तरीय एजेंटों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के तहत गणना प्रपत्र एकत्र किए जाने के बाद तैयार किए गए मसौदा रोल पर कोई आपत्ति या दावा दर्ज नहीं किया है। हालाँकि, इसी अवधि के दौरान 10,570 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं, जिनमें से 127 से ज्यादा आपत्तियों का निपटारा सात दिनों के बाद किया गया। चुनाव आयोग को 54,432 फॉर्म 6 भी प्राप्त हुए हैं, जो 18 वर्ष की आयु के बाद नए मतदाताओं के पंजीकरण से संबंधित हैं। चुनाव आयोग ने अपने दैनिक बुलेटिन में दोहराया है कि ष्एसआईआर के आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित होने वाली मसौदा सूची से किसी भी नाम को ईआरओध्एईआरओ द्वारा जाँच करने और निष्पक्ष एवं उचित अवसर दिए ।

मानहानि केस में मेधा पाटकर की सजा बरकरार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली एक राहत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की दोषसिद्धि की पुष्टि की। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस मामले में पाटकर पर लगाया गया एक लाख रुपये का जुर्माना रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों पर विचार करते हुए लगाया गया जुर्माना रद्द किया जाता है और हम आगे स्पष्ट करते हैं कि पर्यवेक्षण आदेश प्रभावी नहीं होगा। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, जिसमें पाटकर को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें हर तीन साल में एक बार निचली अदालत में पेश होना होगा। परिवीक्षा अपराधियों के लिए एक गैर–हिरासत दृष्टिकोण के रूप में कार्य करती है, जिससे सजा को सशर्त निलंबित किया जा सकता है। कारावास के बजाय, दोषी व्यक्ति को अच्छे आचरण की गारंटी वाले बांड के तहत रिहा किया जाता है। उच्च न्यायालय ने 29 जुलाई को 70 वर्षीय पाटकर को दी गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा ।

संपादकीय

पीड़िताओं ने सामने आने का साहस किया

बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवाा को रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 48 वर्षीय एक घरेलू सहायिका ने कई दफा रेप करने का आरोप लगाया था। बीते साल उस पर चार मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से पहले मामले में दोषी ठहराया गया है। उस पर आईपीसी की धाराएं 376 (2के) (प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा रेप), 376(2)(एन) (बार–बार रेप) 354(ए) (कपड़े उतारने के लिए हमला या बल प्रयोग), 354(सी)(ताकझांक), 506 (सबूतों को गायब करना), सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(ई) लगाई गई। 1632 पों की चार्जशीट के साथ इलेक्ट्रानिक व अन्य 183 सबूत पेश किए गए। बीते साल कर्नाटक सैक्स स्कैंडल के उछलने के बाद प्रज्वल का नाम सामने आया था, उस पर पचास से ज्यादा महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। पीड़ित अमूमन हासन, मैसूर व होलेनरासीपुर व करीबी इलाकों की हैं। हासन के इस सांसद के वहीं के स्टेडियम में सैकड़ों की तादाद में बिखरे मिले पेन ड्राइवों में तकरीबन तीन हजार सेक्स क्लिप व तस्वीरें मिलते ही मामले ने तूल पकड़ लिया था। कई वीडियो वह खुद बना रहा था। वीडियो वायरल होते ही वह देश छोड़ कर भाग गया। प्रधानमंत्री रहे दादा, मुख्यमंत्री रहे चाचा और मंत्री पिता का यह इंजीनियर बेटा 2019 में देश में तीसरा सबसे कम उम्र का सांसद बनने पर चर्चा में आया था। दादा के चेताने पर जर्मनी से लौटा तो एयरपोर्ट से ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पैसों और हैसियत के बल पर महिलाओं के साथ हैवानियत करने वाले की ताकत का ही भय है कि पचास में से केवल चार पीड़िताओं ने सामने आने का साहस किया। हालांकि पहले वह खुद को बेकसूर और आरोपों को झूठा बता रहा था। मगर पकड़े जाने के बाद उसने काड़ टीवी चौनल को भेजे वीडियो में दादा, मां–बाप, जनता दल (सेक्युलर) के कार्यकर्ताओं व राज्य के लोगों से माफी मांगी। लोगों में अपराधियों के प्रति गुस्से के चलते मामले को दबाया नहीं जा सका। बेशक, यह न्याय प्रक्रिया की ताकत है जिसने राज्य चलाने वालों की विकृति को न सिर्फ उधेड़ा, बल्कि कमजोर वर्ग की उस स्त्री को न्याय देकर छिपी बैठीं पीड़िताओं को न्याया का भरोसा दिया है। हालांकि अभी दोषी ऊपरी अदालत जाने को स्वतंत्र है। वहां तक मामला जाने और सलाखों के पीछे जाने में सालों लग सकते हैं, जिससे बच जाना जरूरी हैं। ताकतवर दोषियों को सजा दिला कर कड़ा संदेश देना बेहद जरूरी है।

राहुल गांधी ने बम फोड़ दिया

1 अगस्त को राहुल गांधी ने चेतावनी दे दी थी कि उनके पास चुनाव में वोट चोरी के पक्के सबूत हैं। जब वे इन्हें सार्वजनिक करेंगे तो एटम बम फूटेगा। सात अगस्त की दोपहर जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेंस की, तो वाकई बड़ा धमाका हो गया। इस प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ही आंकड़ों के जरिए साबित कर दिया कि कर्नाटक की एक विधानसभा सीट में किस तरह 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट पड़े हैं। राहुल गांधी का दावा है कि जिस तरह केवल इस एक सीट पर धांधली की गई है, वह असल में एक आसान तरीका है, जो पूरे देश में कहीं भी आजमाया जा सकता है, बल्कि आजमाया जा चुका है। राहुल गांधी ने इस प्रेस कांफ्रेंस को श्वोट चोरीश का शीर्षक दिया। जिसमें मीडिया के सामने उन्होंने दिखाया कि भाजपा बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में छह में पिछड़ गई, लेकिन महादेवपुरा में उसे एकतरफा वोट मिला। श्री गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची के पूरे आंकड़े पत्रकारों के सामने पेश किए। 7 फीट से ऊंचे मतदाता सूची के इस पुलिंदे की पूरी पड़ताल में कांग्रेस की एक टीम को कुल छह महीने का समय लगा है। अगर कागज की जगह ये सूची चुनाव आयोग की तरफ से डिजीटली और वह भी मशीन के पढ़ने योग्य फार्म में उपलब्ध कराई जाती, तो शायद यह पड़ताल आसान होती। मगर राहुल गांधी का दावा है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को श्मशीन के पढ़ने योग्यश (मशीन रीडेबल) डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा है ताकि ये सब पकड़ा नहीं जा सके। फिर भी कांग्रेस ने अभी एक ही संदिग्ध नतीजे वाली सीट का विश्लेषण किया तो हतप्रभ करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। भाजपा द्वारा जीती गई इस सीट पर 1,00,250 मतों की चोरी की गई, ऐसा कांग्रेस का दावा है। इन एक लाख दो सौ पचास मतों के विश्लेषण में सामने आया कि 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए, 40,009 फर्जी पतों का इस्तेमाल हुआ, 10,452 वोटर बड़ी संख्या में एक ही पते पर रजिस्टर किए गए, 4,132 वोटर बिना फोटो या अवैध फोटो के साथ जोड़े गए, 33,692 नए वोटर फॉर्म–6 का गलत इस्तेमाल कर जोड़े गए। एक ही पते पर कहीं 40 कहीं 50 लोगों के वोटर आईडी बने हैं। एक ही नाम से कई मतदाता पहचान पत्र बने हैं, जिनमें कहीं कर्नाटक, कहीं महाराष्ट्र, कहीं उत्तरप्रदेश का पता दर्ज है। कई जगहों पर नाम एक थे, फोटो अलग–अलग थे। कई कार्ड्स में मकानों के पते पर शून्य लिखा है। कई में पिता के नाम पर अंग्रेजी के अक्षर अजीबोगरीब क्रम में लिख दिए गए हैं। फार्म 6, जिसके उपयोग से नए मतदाताओं के कार्ड बनते हैं और फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में आता है, इस फार्म 6 के तहत 70, 80 साल के मतदाताओं के कार्ड भी बने हैं, जबकि कायदे से इसमें 18 साल वाले वोटर होने चाहिए। इस तरह के फर्जीवाड़े से महज एक सीट पर लाख से अधिक वोट बढ़ाए गए और मजे की बात ये है कि यहां भाजपा की जीत हुई है। अकाट्य तथ्यों और सबूतों के साथ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की धांधली का उदाहरण देश के सामने पेश कर दिया। फिर अपनी बात दोहराई कि जो खेल इस एक सीट पर हुआ है, उसी तरह की आशंकाएं महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में भी बनी हैं। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जीत की उम्मीद थी, एक्जिट पोल भी यही दर्शा रहे थे। सत्ता पर बैठे हर राजनैतिक दल के खिलाफ एंटी इनकमबेंसी सामान्य बात है, लेकिन भाजपा इससे हमेशा कैसे बच निकल रही है, इसका पूरा खुलासा राहुल गांधी ने किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में धांधली की बात हम पहले भी कहते थे, लेकिन पूरे तथ्य नहीं थे, इसलिए झिझकते थे। मगर अब राहुल गांधी ने यह कहने में कोई संकोच नहीं किया कि विपक्ष कभी न कभी सत्ता में आएगा और तब हर छोटे–बड़े जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी। कायदे से इस समय तीनों चुनाव आयुक्तों को अपना इस्तीफा देकर इस धांधली की स्वतंत्र जांच का रास्ता तैयार करना चाहिए। क्योंकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के उसके दावे पर ये एक लाख 250 फर्जी वोट सवाल उठा रहे हैं। मगर हमेशा की तरह राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा ने तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब देना शुरु कर ही दिया है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपात्र मतदाताओं के जुड़े और पात्र मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप पर शपथ पत्र मांगा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को शुक्रवार 1 से 3 बजे तक मिलने का समय भी दिया है। जब इस बारे में राहुल गांधी से सवाल हुए तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि श्मैं एक राजनेता हूं। मैं लोगों से जो कहता हूं वह मेरा वचन है। मैं इसे सार्वजनिक रूप से सभी से कह रहा हूं। इसे शपथ के रूप में लें। यह उनका डेटा है, और हम उनका डेटा दिखा कर रहे हैं। यह हमारा डेटा नहीं है। यह चुनाव आयोग का डेटा है। राहुल गांधी के इस बड़े खुलासे के बाद अब चुनाव आयोग के पाले में गेंद चली गई है कि वह या तो इन सबूतों को गलत साबित करे या फिर गलती की जिम्मेदारी स्वीकार करे। अगर चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता है,।

संसद संवाद की बजाय संघर्ष का अखाड़ा कब तक?

ललित

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर संसद में गतिरोध जारी है, जिससे कामकाज बाधित हो रहा है। आज संसद का दृश्य सार्थक संवाद की बजाय किसी अखाड़े से कम नहीं लगता। बहस के स्थान पर बैनर, तख्तियां और नारों की गूंज सुनाई देती है। संसद जहां नीति निर्माण होना चाहिए, वहां प्रतिदिन कार्यवाही स्थगित हो रही है। यह विडंबना है कि जनप्रतिनिधि जिन मुद्दों को लेकर चुने जाते हैं, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की बजाय वे मेजें थपथपाने, वेल में उतरने और माइक बंद कराने में लगे हैं। संसद का हंगामा केवल दृश्य नहीं, एक राजनीतिक पतन की ओर संकेत करता है। जब एक ओर सरकार संवाद से बच रही है और दूसरी ओर विपक्ष केवल दिखावटी विरोध में लिप्त हंगामें बरपा रहा है, इन त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थितियों में देश की जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। विपक्ष और सत्ता के बीच जारी इस टकराव में बहस के बजाय बहिष्कार और गतिरोध हावी हो चुका है। मानसून सत्र की शुरुआत उम्मीदों से भरी थी, नए विधेयकों, जनहित की बहसों और लोकतांत्रिक विमर्शों की। लेकिन यह सत्र भी पुराने ढर्रे पर चल पड़ा, विरोध, स्थगन, नारेबाजी और हंगामे की भेंट चढ़ता लोकतंत्र। विपक्ष बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा चाहता है। इसमें ईवीएम की पारदर्शिता, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही मणिपुर की स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, पेगासस जासूसी, किसानों की समस्याएं और हाल ही में आई बाढ़ एवं आपदा राहत जैसे मुद्दे भी विपक्ष के एजेंडे में हैं। लेकिन विपक्ष इन और ऐसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा का माहौल बनाने की बजाय सरकार को घेरने की मानसिकता से ग्रस्त है। संसद की प्रासंगिकता तभी है जब उसमें देश की सच्चाइयों की प्रतिध्वनि हो और विपक्ष इसमें सकारात्मक भूमिका निभाये। गतिरोध के कारण दर्जनों विधेयक लंबित हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल, महिला आरक्षण बिल, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा, कृषि कानूनों में संशोधन, आदि। ये सब विधेयक केवल कानून नहीं हैं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन से जुड़े ज्वलंत प्रश्न हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, विपक्ष सार्थक बहस से भाग रहा है या बहस में अड़ंगा डाल रहा है। सत्ता पक्ष भी कोई बीच का रास्ता निकालता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों की यह रस्साकशी देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य को कमजोर कर रही है। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। लेकिन, इसका असर संसद के कामकाज पर पड़ रहा है। दोनों सदनों का कीमती वक्त हंगामे में जाया हो रहा है और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले वर्षों में इस तरह की गतिविधियां आम हो गई हैं। विपक्ष चाहता है कि सरकार एसआईआर पर चर्चा कराए। लेकिन, सरकार नियमों का हवाला देकर कह रही है कि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। जवाब में, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी 2023 की एक रूलिंग निकाल कर उपसभापति को पत्र लिख दिया है। दोनों पक्ष नियमों के सवाल पर अड़े हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि ये नियम सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए हैं, न कि कामकाज ठप्प कराने के लिए। मानसून सत्र शुरू होने के पहले ही अंदाजा था कि एसआईआर पर हंगामा होगा। इसके पीछे विपक्ष की अपनी आशंकाएं हैं। शुरुआत से ही यह प्रक्रिया विवादों में रही है। आधार और वोटर कार्ड को मान्य डॉक्युमेंट्स में शामिल न करने से लेकर बड़ी संख्या में लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने तक, इसमें कई पेच फंसे हैं। चुनाव आयोग ने संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और इसमें 65 लाख नाम हटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की पूरी जानकारी मांगी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले दिनों कहा था कि अगर विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहता है, तो देशहित में सरकार के सामने विधेयक पारित कराने की मजबूरी होगी। लेकिन, लोकतंत्र के लिए यही बेहतर होगा कि दोनों पक्ष सदन का इस्तेमाल रचनात्मक बहस के लिए करें। आम नागरिक संसद से समाधान की उम्मीद करता है, न कि शोरशराबा। जब लाखों युवा रोजगार की बाट जोह रहे हैं, किसान कर्ज में डूब रहे हैं, और आमजन महंगाई से त्रस्त है, तब संसद में ठहाके नहीं, तकलीफों की चर्चा जरूरी है। यह सवाल अब बार–बार

उठ रहा है कि क्या संसद केवल दिखावटी बन गई है? अगर सरकार विपक्ष को केवल बाधा मानकर चलती है और विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध करता है, तो लोकतंत्र की आत्मा मरती है। जैसाकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, "संसद को ठप्प करना आसान है, लेकिन संसद को चलाकर देश की उम्मीदों को साधना ही असली लोकतंत्र है।" चुनाव आयोग एसआईआर की जरूरत को बता चुका है और शीर्ष अदालत ने भी उसे माना है। यह जरूरी भी है, क्योंकि भ्रष्ट वोटरों से चुनी जाने वाली सरकारें भी भ्रष्ट ही होती है। इसलिये चुनाव की इस विसंगति की सफाई होना जरूरी है, इस पर चर्चा की मांग को लेकर सत्ता पक्ष–विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है तो बातचीत से इसका हल निकालना होगा ताकि संसद का कामकाज सुचारुरूप से चल सके। लोकतंत्र में सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन इसमें विपक्ष का सहयोग भी अपेक्षित होता है, दोनों को अपना यह दायित्व समझना चाहिए। संसद का हर सत्र, हर मिनट करदाताओं की गाढ़ी कमाई से चलता है। हर व्यवधान लाखों रुपये की बर्बादी है। यह नैतिक रूप से भी चिंताजनक है कि जनप्रतिनिधि बहस से अधिक हंगामे में समय गंवा रहे हैं। समाधान यही है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बात सुने, संवाद को प्राथमिकता दे। विपक्ष भी रचनात्मक विरोध करे, अनावश्यक बहिष्कार से बचे। लोकतंत्र बहस से ही मजबूत होता है, बहिष्कार से नहीं। वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा होनी चाहिए। जरूरी विधेयकों पर बहस होनी चाहिए। संसद को संकल्प का मंच बनना चाहिए, संग्राम का नहीं। जब तक संसद जनहित के सवालों पर गूंजेगी नहीं, तब तक लोकतंत्र अपंग ही रहेगा। जैसा कि डॉ. राधाकृष्णन ने कहा था–संसद केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, यह राष्ट्र के विवेक की आवाज है।' लेकिन जब यह विवेक ही हंगामे में दब जाए, तो संविधान की आत्मा कराह उठती है। आज जरूरत है कि संसद को नई दिशा, नया दृष्टिकोण और नई मर्यादा मिले। संसद की गरिमा केवल आसनों से नहीं, आचरण से बनती है। संसद में वही नेता दिशा दे सकते हैं, जो अपने निजी या दलगत हित से ऊपर उठकर राष्ट्रहित की सोच रखते हैं। जब तक संसद के सदस्य यह नहीं समझेंगे कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं, न कि अपने दल के प्रचारक, तब तक दिशा भटकती रहेगी। विपक्ष लोकतंत्र की आंख है। लेकिन जब यह आंख केवल अंधविरोध में अंधी हो जाए, तो लोकतंत्र की दृष्टि धुंधली हो जाती है। विपक्ष को सद्बुद्धि दे सकता है, जनता का दबाव। जब जनता यह स्पष्ट रूप से जताए कि उसे रचनात्मक, नीति आधारित विपक्ष चाहिए न कि नारेबाज नेता, तब विपक्ष को भी सुधरना पड़ेगा। विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या वह जनता की लड़ाई लड़ रहा है या केवल सत्तालोलुप राजनीति कर रहा है? मीडिया को चाहिए कि वह हंगामे को महिमामंडित करने के बजाय, नीति और तर्क आधारित बहस को आगे बढ़ाए। संसद में विवाद होना लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन वही विवाद अगर दिशा विहीन हो जाए, तो वह कमजोरी बन जाता है। आज जरूरत है कि संसद की गरिमा को पुनर्स्थापित किया जाए, विपक्ष अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाए और सरकार भी अहंकार छोड़कर संवाद को अवसर दे। संसद यदि सचमुच "लोक का मंदिर" है, तो वहाँ केवल सत्ता की पूजा नहीं, लोकमंगल की बात होनी चाहिए।

मोदी एक बार कह दें कि ट्रंप ने जंग नहीं रूकवाई

अजीत द्विवेदी

संसद के मानसून सत्र का इंतजार सबको था। इंतजार इसलिए था क्योंकि सरकार ने पहलगाम कांड और आपेरशन सिंदूर के बाद विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की अपील पर ध्यान नहीं दिया था। संसद में खड़े होकर विपक्ष को जवाब देने और देश के नागरिकों को इसकी सचाई बताने की बजाय सरकार दुनिया भर के देशों में डेलिगेशन भेज कर उनके सामने अपना पक्ष रख रही थी। तभी जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई और यह तय हुआ कि दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार, 28 जुलाई को पहलगाम कांड व आपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी तो उम्मीद थी कि इनसे जुड़े समूचे घटनाक्रम की सचाई सामने आएगी। सरकार हर पहलू के बारे में जानकारी देगी। विपक्ष जो सवाल पहले से उठा रहा है और जो सदन में सवाल उठाए जाएंगे, उनका वस्तुनिष्ठ तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि दो दिन की लंबी चर्चा और प्रधानमंत्री के लंबे भाषण के बाद भी बहस अधूरी ही रह गई। इस बहस के बाद यह धारणा भी मजबूत हुई कि भारत में संसदीय बहसों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और सारी संसदीय बहस सिर्फ राजनीति साधने और चुनावी लाभ के लिए होती हैं। किसी भी सभ्य लोकतंत्र में संसदीय बहसें ऐसी नहीं होती हैं। भारत में भी कोई संविधान सभा की बहस के दस्तावेज पढ़े तो उसे भी आज जो हो रहा है उस पर शर्म ही आएगी।

बहरहाल, पहलगाम कांड और आपरेशन सिंदूर से जुड़े कौन से सवाल थे, जिनके वस्तुनिष्ठ जवाब की जरुरत थी, उस पर आने से पहले एक रूपक के जरिए इस बहस को समझते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति उनसे बिजली नहीं आने की शिकायत कर रहा था। वह व्यक्ति कह रहा था कि सिर्फ तीन घंटे बिजली आती है और अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर तक यह बात सुनने के बाद माननीय बिजली मंत्री ने अपने गले में पड़ी ढेर सारी मालाएं निकालीं और जोर से नारा लगाया, जय श्रीराम! बात वही खत्म हो गई। लोकसभा में पहलगाम कांड और आपरेशन सिंदूर पर सत्तापक्ष यानी भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सभी नेताओं का भाषण इसी श्रेणी का था। सवालों का जवाब देने की बजाय सत्तापक्ष के लगभग सारे वक्ता सेना के शौर्य का गुणगान कर रहे थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे, अपनी छाती ठोक रहे थे और 77 साल पहले वाली सरकार की कमियां गिना रहे थे।

सोचें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीब एक सौ मिनट के भाषण में 14 बार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम लिया! क्या पहलगाम कांड और आपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा में देश के लोग यही सुनना चाहते थे? नेहरू की गलतियां थीं या इंदिरा गांधी ने गलती की या उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने गलतियां कीं तभी तो देश की जनता ने भाजपा और नरेंद्र मोदी को मौका दिया है! अब तो देश के लोग इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। नेहरू का या इंदिरा गांधी का नाम लेकर किसी भी तात्कालिक मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता है। नेहरू की गलतियां अपनी जगह हैं, जिनके बारे में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी एक सौ साल से बोल रहे हैं। लेकिन लोग तो यह जानना चाहते थे कि पर्यटकों की उतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद पहलगाम घाटी में एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं तैनात था? लोग यह जानना चाहते थे कि आतंकवादी 20 मिनट तक तांडव करते रहे और उतनी देर में एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंचा और आतंकवादियों के जवाब देने के लिए एक भी गोली नहीं चली तो ऐसा क्यों हुआ? यह तो संभव नहीं है कि नेहरू या इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से रोक दिया था? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए था और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री के इतने लंबे भाषण में एक बार भी पहलगाम में मारे गए 26 बेकसूर नागरिकों का जिक्र नहीं आया।

देश के लोग जानना चाहते थे कि आपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें भारतीय सेना ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया तो फिर 88 घंटे के भीतर सीजफायर क्यों हो गया? जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशक यानी डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से गुहार लगाई कि पाकिस्तान अब और हमला नहीं झेल सकता है तो युद्धविराम हो गया। सवाल है कि पाकिस्तान मजबूर था कि वह हमारा हमला नहीं झेल पा रहा था लेकिन हमारी क्या मजबूरी थी? हमने क्यों सीजफायर स्वीकार कर लिया? अगर स्वीकार किया तो पाकिस्तान के सामने क्या शर्तें रखीं और क्या उसने हमारी कोई शर्त स्वीकार की? दुनिया के तमाम सामरिक और रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि भारत को दो तीन दिन और हमले जारी रखने चाहिए थे ताकि पाकिस्तान का सैन्य ढांचा स्थायी रूप से खत्म हो और उसके सैन्य नेतृत्व की कमजोरी पाकिस्तान की जनता के सामने जाहिर हो। लेकिन इसका उलटा हुआ। बिना शर्त युद्धविराम की वजह से पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को छाती ठोक कर जीत का दावा करने का मौका मिला और आज पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व पहले से ज्यादा मजबूती और ताकत के साथ भारत विरोधी गतिविधियों में लगा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी उसकी प्रतिष्ठा कम होने की बजाय बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ कि भारत जीतता हुआ पक्ष था लेकिन उसने बिना शर्त सीजफायर कर लिया, इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया।

सीजफायर कराने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे का भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने सीजफायर नहीं कराई। वे संसद में वही बोले, जो ब्राजील में जी 7 देशों के सम्मेलन में बोले थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई थी। उन्होंने यह भी दोहराया कि अमेरिका के उप राष्ट्रपति जीडी वेंस ने उनसे कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है तो उन्होंने कहा कि हम उससे बड़ा हमला करेंगे। सवाल है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया और हमें हमला करने की जरुरत नहीं पड़ी? कुछ तो हुआ परदे के पीछे, जिसके बाद सीजफायर हुआ! प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बताना चाहिए था कि क्या हुआ, जिसकी वजह से बिना शर्त सीजफायर की नौबत आई। विडम्बना यह है कि जिस समय प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रूकवाई लगभग उसी समय अमेरिका में ट्रंप ने दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जंग रूकवाई। ध्यान रहे दुनिया का कोई नेता सीजफायर का श्रेय नहीं ले रहा है, सिर्फ ट्रंप ले रहे हैं। इसलिए दुनिया कि किसी नेता ने नहीं रूकवाई कहने की बजाय अगर प्रधानमंत्री मोदी एक बार कह दें कि ट्रंप ने जंग नहीं रूकवाई तो बात खत्म हो। लोग यह सुनना चाहते थे लेकिन यह नहीं कहा गया।

एक और अहम बात जो पूरी चर्चा में मिसिंग रही वह ये है कि भारत को कितना नुकसान हुआ। पेंसिल टूटने की बात कही गई लेकिन यह भारत के प्रतिरक्षा प्रमुख यानी सीडीसी जनरल अनिल चौहान की बात का स्पष्टीकरण नहीं है और न जकार्ता दूतावास के भारत के डिफेंसे अताशे कैप्टेन शिवकुमार की बात का जवाब है। दोनों ने भारत के नुकसान की बात कही थी। कैप्टेन शिवकुमार ने तो नुकसान के लिए राजनीतिक फैसले को जिम्मेदार बताया था। लेकिन पूरी बहस में सरकार की ओर से इसका जवाब नहीं दिया गया। भारत को कितना और क्या नुकसान हुआ यह बताया जाना चाहिए था या फिर यह कहा जाना चाहिए था कि सेना के दोनों अधिकारियों ने जो कहा वह सही नहीं है।

भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीमित जंग में चीन सक्रिय भागीदार था और यह बात भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि चीन ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। उसने पाकिस्तान के जरिए भारत के खिलाफ अपने हथियारों का परीक्षण किया। भारत के खिलाफ युद्ध में चीन की सक्रिय भागीदारी के बावजूद रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों चीन के दौरे पर गए और जब आपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हुई तो उस बारे में कुछ नहीं कहा गया। यह सही है कि इतने बड़ा घटनाक्रम के बावजूद भाजपा और नरेंद्र मोदी को कोई राजनीतिक नुकसान होता नहीं दिख रहा है। लेकिन समर्थक वर्ग को परवाह नहीं है क्या इस वजह से इतने अहम सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा?

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में नया तनाव

विनीत नारायण

हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ और रूस से तेल और हथियारों की खरीद के लिए अतिरिक्त दंड की घोषणा की। यह कदम भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों में महत्त्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से तब जब दोनों देश एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत और रूस को मृत अर्थव्यवस्था (डेड इकानमी) कह कर निशाना बनाया और भारत के उच्च टैरिफ और गैर–मौद्रिक व्यापार बाधाओं को इसका कारण बताया। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने वाली आक्रामक टैरिफ नीतियों को अपनाया है। 7 अगस्त, 2025 से लागू होने वाले 25 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप ने इसके लिए भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद को प्रमुख कारण बताया। उनके अनुसार, भारत रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है, जो यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के समय में अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, ट्रंप ने भारत के उच्च टैरिफ (जिसे उन्होंने दुनिया में सबसे अधिक बताया) और गैर–मौद्रिक व्यापार बाधाओं की भी आलोचना की। ट्रंप ने पहले 20–25 प्रतिशत टैरिफ की संभावना जताई थी, लेकिन अंतिम घोषणा में अतिरिक्त दंड भी शामिल किया गया। यह कदम भारत के फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, र प्रतिशत और आभूषण और आटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जो अमेरिका के साथ भारत के व्यापार के महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। कांग्रेस नेता और लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के मृत अर्थव्यवस्था वाले बयान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, हां, ट्रंप सही हैं। हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत है, सिवाय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के। मुझे खुशी है कि ट्रंप ने यह तथ्य सामने रखा। दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। भाजपा ने अडानी को मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। राहुल ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए, विशेष रूप से नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी अर्थव्यवस्था के पतन के कारण बताए। उन्होंने यह भी पूछा कि ट्रंप के भारत–पाकिस्तान सीजफायर को लेकर बार–बार किए जा रहे दावों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है? कांग्रेस पार्टी ने इस टैरिफ को भारत की विदेश नीति की विफलता के रूप में चित्रित किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, राहुल गांधी ने पहले ही इस बारे में चेतावनी दे दी थी। यह टैरिफ हमारी अर्थव्यवस्था, निर्यात, उत्पादन और रोजगार पर असर डालेगा। हम अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स निर्यात करते हैं, और 25 प्रतिशत टैरिफ से ये महंगे हो जाएंगे जिससे मांग कम होगी और उत्पादन तथा रोजगार पर असर पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए और टैरिफ को भारत के व्यापार, एमएसएमई और किसानों के लिए हानिकारक बताया। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरे दिनों की शुरुआत बताया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रंप को व्हाइट हाउस का जोकर कह कर उनकी आलोचना की। वहीं, अर्थशास्त्रियों ने इस टैरिफ के भारत की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव को लेकर मिश्रित राय व्यक्त की है। कुछ का मानना है कि इसका प्रभाव सीमित होगा जबकि अन्य ने दीर्घकालिक नुकसान की चेतावनी दी है। इंवेस्टमेंट इनफार्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया (इक्रा) की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, प्रस्तावित टैरिफ और दंड हमारी अपेक्षा से अधिक हैं, और इससे भारत की जीडीपी की वृद्धि पर असर पड़ सकता है। प्रभाव की गंभीरता दंड के आकार पर निर्भर करेगी। अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया (ईवाई) के व्यापार नीति विशेषज्ञ अग्नेर सेन ने कहा, टैरिफ से समुद्री उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, चमड़ा और आटोमोबाइल जैसे क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे। ये क्षेत्र भारत–अमेरिका व्यापार में मजबूत हैं, और टैरिफ से इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। फाउंडेशन फार इकोनामिक डवलपमेंट के राहुल अहलूवालिया ने चेतावनी दी कि टैरिफ भारत को वियतनाम व चीन जैसी अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कमजोर कर सकता है। उनके अनुसार, निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं के भारत की ओर स्थानांतरण की संभावना नहीं है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने आशावादी रुख भी अपनाया है। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा, हालांकि यह कदम दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे निर्यात पर असर डालेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि यह अल्पकालिक घटना होगी और दोनों पक्ष जल्द ही एक स्थायी व्यापार समझौते पर पहुंच जाएंगे। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर सतर्क और संयमित रुख अपनाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा, हम राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत ने एक दशक में फ्रैजाइल फाइव से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया है। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि भारत तत्काल जवाबी टैरिफ लगाने की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएगा। एक सूत्र ने कहा, चुप्पी सबसे अच्छा जवाब है। हम बातचीत की मेज पर इस मुद्दे को हल करेंगे। कुल मिलाकर 25 प्रतिशत टैरिफ और अतिरिक्त दंड ने भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों में नया तनाव पैदा कर दिया है। राहुल गांधी और विपक्ष ने इसे सरकार की आर्थिक और विदेश नीति की विफलता के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि अर्थशास्त्रियों ने इसके मिश्रित प्रभावों की ओर इशारा किया है।

ट्रैक्टर–मिक्सर ने बाइक में मारी टक्कर, दंपती और मासूम बच्ची समेत पांच की मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी के श्रावस्ती में सोमवार की सुबह भीषण हादसा हो गया। बदला चौराहा से शंकरपुर मार्ग पर ट्रैक्टर–मिक्सर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दंपती और दो बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि, एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घायल को अस्पताल पहुंचाया। हादसा हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र में हरबंसपुर के पास हुआ। मूल रूप से बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र के मंगलपुरवा निवासी विजय कुमार वर्मा (32) सुबह अपनी पत्नी सुनीता देवी (28), मंगलवती (40), नीतू (30), नीतू की बहन ज्ञानवती (09) और एक साल की मासूम बच्ची के साथ बाइक से रुपईडीहा थाना क्षेत्र के मधनगरा जा रहे थे।

अस्पताल में मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया

हरबंशपुर पुलिस चौकी के पास ट्रैक्टर–मिक्सर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में विजय, मंगलवती, नीतू और ज्ञानवती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सुनीता और एक साल की मासूम बच्ची घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। वहां मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने ट्रैक्टर–मिक्सर को कब्जे में लिया

हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वह रोते–बिलखते मौके पर पहुंचे। एसपी घनश्याम चौरसिया ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल महिला का हाल जाना। वहीं एएसपी मुकेश चंद्र उत्तम और सीओ सतीश शर्मा ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने ट्रैक्टर–मिक्सर को कब्जे में लिया है। हालांकि, चालक मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है।

विधानमंडल सत्र, बदला रहेगा शहर का ट्रैफिक मुख्य शहर की तरफ

लखनऊ, (संवाददाता)। विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। इस दौरान यातायात की सुगमता को ध्यान में रखते हुए विधानसभा की ओर जाने वाले मार्ग पर आम वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। डायवर्ट रूट से आवागमन हो सकेगा। यातायात पुलिस के मुताबिक सत्र के दौरान विधान भवन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष विधानसभा, सभापति विधान परिषद, उप मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल, सभी मंत्री, विधायक व विधान परिषद सदस्य विधान भवन पहुंचेंगे। इस दौरान राजनैतिक दलों की ओर से विधानसभा के समक्ष धरना, प्रदर्शन की संभावना और यातायात के सुगम संचालन को ध्यान में रखते हुए 11 अगस्त से सत्र समाप्त होने तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। सत्र के दौरान सामान्य यातायात के लिए किए गए डायवर्जन मार्ग पर इमरजेंसी सेवा के वाहन जा सकेंगे। यातायात पुलिस के मुताबिक किसी जन–सामान्य की चिकित्सकीय आवश्यकता, एंबुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस, स्कूली वाहन आदि प्रतिबंधित मार्ग से भी जा सकेंगे। इसके निर्देश ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय पुलिस को दे दिए गए हैं। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर–9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है। – बंदरियाबाग चौराहा से सामान्य यातायात राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज चौराहा, जीपीओ मोड़, विधानसभा की ओर नहीं जा सकेगा। इसे लालबत्ती चौराहा, कैंट या गोल्फ क्लब चौराहा, 1090 चौराहा होकर गंतव्य को जाना होगा।

– डीएसओ चौराहे से हजरतगंज, जीपीओ पार्क, विधानसभा मार्ग की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। इसे पार्क रोड, मेफेयर तिराहा होकर गंतव्य को जाना होगा। रॉयल होटल चौराहे से विधानसभा के सामने से हजरतगंज चौराहे की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। इसे कैसरबाग चौराहा, परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, चिरैयाझील या बर्लिंगटन चौराहा, सदर ओवरब्रिज, कैंट होकर जाना पड़ेगा। संकल्प वाटिका पुल के नीचे तिराहे से महानगर की तरफ से आने वाली रोडवेज, सिटी बसें सिकंदरबाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा, विधानसभा की ओर नहीं आ सकेंगी। इन बसों को बैकुंठ धाम, 1090 (गांधी सेतु) चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा, लालबत्ती चौराहा, कैंट होते हुए अपने गंतव्य को भेजा जाएगा। केकेसी तिराहा से चारबाग की तरफ से आने वाली रोडवेज, सिटी बसें हुसैनगंज चौराहा, रॉयल होटल चौराहा, विधानसभा की ओर नहीं आ सकेंगी। इन्हें लोको चौराहा, कैंट या बर्लिंगटन चौराहा से कैसरबाग होकर जाना पड़ेगा। गोमतीनगर की तरफ से आने वाली रोडवेज, सिटी बसें सिकंदरबाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा, विधानसभा की ओर नहीं जा सकेंगी। इन्हें बैकुंठ धाम, संकल्प वाटिका ओवरब्रिज, चिरैयाझील तिराहा होकर कैसरबाग होते हुए तथा 1090 (गांधी सेतु) चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा, लालबत्ती चौराहा, कैंट होते हुए गंतव्य को जाना पड़ेगा। सिकंदरबाग चौराहा से हजरतगंज, विधानसभा की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेगा।

संक्षिप्त खबरें

कड़ी सुरक्षा के बीच मिश्रिख और महमूदाबाद में मतदान जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। सीतापुर में महमूदाबाद और मिश्रिख नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक आठ फीसदी मतदान हुआ है। महमूदाबाद में 53 और मिश्रिख में 25 बूथों पर मतदान हो रहा है। महमूदाबाद के 52191 और मिश्रिख के 16790 मतदाता अपना नया अध्यक्ष चुनेंगे। एडीएम व उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि दोनों निकायों को पांच–पांच सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही दो–दो जोन बनाए हैं। शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। इस दौरान डीएम अभिषेक आनंद , एसपी अंकुर अग्रवाल चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं एडीएम नीतीश सिंह, एएसपी उत्तरी आलोक सिंह व अन्य अधिकारी लगातार पर निरीक्षण कर रहे हैं।

काकोरी कांड की शताब्दी पर कांग्रेस का देशभक्ति से ओतप्रोत जयहिंद यात्रा

लखनऊ, (संवाददाता)। काकोरी कांड की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर ''क्रांति दिवस'' की पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने हरदोई रोड स्थित काकोरी शहीद स्मारक पर भव्य जयहिंद यात्रा निकाली। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डेय मुख्य अतिथि थे, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अध्यक्षता की। हजारों कांग्रेसजनों ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए अमर क्रांतिकारियोंकृचन्द्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेन्द्र लाहिड़ीकृकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।इस अवसर पर अविनाश पाण्डेय ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों का योगदान सदैव इतिहास में अमर रहेगा। उन्होंने पूरे अगस्त माह को क्रांति का महीना बताते हुए कहा कि इसी महीने में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में गूंज उठा था।

प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने युवाओं से अपील की कि वे शहीदों के समर्पण से प्रेरणा लेकर देशभक्ति की भावना को जीवित रखें।विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ''मोना'' ने कहा कि अमर शहीदों के संघर्ष ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के साथ ही राष्ट्रीय एंकता की नींव भी डाली। कार्यक्रम संयोजक मो. हनीफ खान ने अतिथियों और सहभागियों का स्वागत एवं धन्यवाद किया। कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की भावना को बढ़ावा देते हुए आम का पौधा भी रोपा गया।विशिष्ट रूप से, जयहिंद यात्रा से पूर्व कांग्रेस नेता पुराना किला स्थित मांटेसरी स्कूल पहुंचे जहां स्वतंत्रता संग्राम की नायिका दुर्गा देवी वोहरा (दुर्गा भाभी) की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया।राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पाण्डेय, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने स्कूल परिसर में स्वतंत्रता संग्राम शोध केन्द्र का भ्रमण किया और जर्जर भवन की मरम्मत के प्रयास का आश्वासन दिया।इस प्रकार काकोरी कांड की शताब्दी पर कांग्रेस ने शहीदों को नमन करते हुए देशभक्ति, सामाजिक एकता और जिम्मेदारी का संदेश दिया।

पत्नी के गले पर मारा ब्लेड, बनाया बंधक

लखनऊ, (संवाददाता)। मलिहाबाद के ढकवा गांव निवासी चांदनी ने पति पिंकू पर ब्लेड से गले पर हमला करने का आरोप लगाया है। आरोपी ने डॉक्टर बुलाकर पत्नी को इलाज भी कराया। वहीं, घायल पत्नी को कमरे में पांच दिन तक बंधक बनाए रखने का भी आरोप है। पीड़िता क तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर रविवार को आरोपी पिंकू को गिरफ्तार कर लिया है। चांदनी के मुताबिक चार अगस्त की रात लगभग दस बजे पति ने बेवजह मारा–पीटा और विरोध करने पर हत्या के इरादे से उनके गले पर ब्लेड से वार कर दिया। उन्होंने मदद के लिए शोर मचाया तो पिंकू ने उनका मुंह दबा दिया और डॉक्टर को बुलाकर गले पर टांके लगवा दिए। घटना के बाद आरोपी ने चांदनी को कमरे में बंद कर दिया।

खुद को बलरामपुर अस्पताल का डॉक्टर बता युवती से ऐंठे 10.30 लाख

लखनऊ, (संवाददाता)। पारा निवासी युवती ने खुद को बलरामपुर अस्पताल का डॉक्टर बताने वाले नर नारायण उपाध्याय व उसकी पत्नी गिरजा पर स्वास्थ्य विभाग में बाबू की नौकरी लगवाने के नाम पर 10.30 लाख रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है। डॉक्टर व उसके तीन अज्ञात साथियों पर युवती से छेड़छाड़ करने का भी आरोप है। मामले में पारा पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। युवती के मुताबिक नवंबर 2020 में बलरामपुर अस्पताल में उनकी मुलाकात आरोपी डॉक्टर से हुई थी। आरोपी ने उनकी नौकरी लगवाने की बात कही थी। इसके बदले में उसने दस लाख की मांग की थी। पीड़िता ने तीन लाख डॉक्टर की पत्नी के खाते में ट्रांसफर किए थे, जबकि 7.10 लाख नकद डॉक्टर को नकद दिए थे। पीड़िता ने पूरा भुगतान दो मई 2022 तक किया था, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगी। दबाव बनाने पर आरोपी ने उन्हें बीते आठ जून को मिलने बुलाया। पीड़िता जब पहुंची तो आरोपी व उसके तीन साथियों ने उनसे छेड़छाड़ की फिर तमंचा लहराते हुए सभी भाग निकले। आरोप है आरोपी ने नर नारायण ने खुद को पीजीआई का भी डॉक्टर बताया था। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक मामले की विवेचना चल रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉ. हिमांशु के मुताबिक नर नारायण नाम का कोईडॉक्टर अस्पताल में न तो पूर्व में कार्यरत था और न वर्तमान में है।

हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर सात लोगों से ठगे 1.07 करोड़

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनगर के एल्डिको ग्रीन सिटी निवासी पृथ्वीराज गोस्वामी ने कानपुर नगर के भटपुरवा निवासी संजय कुमार पर उनसे व छह अन्य लोगों से हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर 1.07 करोड़ रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर गोमतीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पृथ्वीराज के मुताबिक कुछ वर्ष पहले ट्रेन में उनकी मुलाकात संजय से हुई थी। धीरे–धीरे उनमें दोस्ती हो गई। कुछ दिन बाद संजय ने उनसे कहा कि वह हाईकोर्ट में उनकी नौकरी लगवा सकता है। इस पर पृथ्वीराज ने भाई विश्वजीत की नौकरी लगवाने की बात कही। इसके बदले संजय ने उनसे 15 लाख रुपये लिए। आरोपी ने यह भी कहा कि वह और भी लोगों की नौकरी लगवा सकता है। ऐसे में पृथ्वीराज ने आरोपी को परिचित बिहार के नालंदा निवासी मुकेश कुमार, राजीव कुमार, गया के अजय कुमार, वीरेंद्र कुमार व विक्रम से मिलवाया। इन सभी ने भी कुल 92.49 लाख रुपये आरोपी को दिए। कुछ दिन बाद आरोपी ने सभी को नियुक्ति पत्र व परिचय पत्र दे दिया। सभी जब हाईकोर्ट पहुंचे तब उन्हें फर्जीवाड़े का पता चला। पुलिस से शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में पृथ्वीराज ने कोर्ट की शरण ली।

संक्षिप्त खबरें

विधवा दिव्यांग महिला की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने इंदिरा भवन स्थित आयोग कार्यालय में विभिन्न जनपदों से प्राप्त 38 शिकायती प्रकरणों पर जनसुनवाई की। इस दौरान पेंशन भुगतान में देरी, अवैध कब्जे, अधिकारी अनुपस्थिति जैसे गंभीर मामलों पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाया।राम आसरे सिंह के सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी और राशिकरण भुगतान में 63 दिन की देरी पर आयोग ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। सहायक कोषाधिकारी जवाहर भवन ने बताया कि सभी देयकों का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन शासनादेश के अनुसार भुगतान अधिकतम तीन दिन में होना चाहिए था। आयोग ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की।फूलकेसरी कश्यप के मामले में नगर निगम लखनऊ का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर अध्यक्ष ने गंभीर असंतोष जताते हुए चेतावनी दी कि अगली सुनवाई पर सक्षम अधिकारी की अनुपस्थिति की स्थिति में नगर आयुक्त के खिलाफ शासन को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगाजनपद बाराबंकी की विधवा दिव्यांग महिला मधु देवी के मामले में आयोग ने विशेष संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन और पुलिस को उनकी भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के कड़े निर्देश दिए हैं।अयोध्या के धनीराम वर्मा के प्रकरण में संविदा समाप्ति के बाद भी भूमि खाली न किए जाने पर आयोग ने क्षेत्राधिकारी अयोध्या को कार्यवाही कर रिपोर्ट के साथ अगली तिथि पर उपस्थित होने का निर्देश दिया।रमेश सिंह और दिनेश कुमार के पेंशन प्रकरणों में अनावश्यक विलंब पर पेंशन विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई गई और त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।आयोग ने अनुपस्थित रहे अन्य विभागीय अधिकारियों पर भी नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में भी सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं होंगे, तो उनके खिलाफ शासन को लिखकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सीतापुर में किसान गोष्ठी एवं हरिशंकरी वृक्षारोपण कार्यक्रम में गोपालकों को मिला

लखनऊ, (संवाददाता)। कृषि विज्ञान केंद्र, कटिया, जनपद सीतापुर के तत्वावधान में 8 अगस्त, 2025 को एक दिवसीय किसान गोष्ठी एवं हरिशंकरी वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें प्रवृद्ध फाउंडेशन ने सहयोग प्रदान किया।इस अवसर पर उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक, प्रवृद्ध फाउंडेशन के निदेशक पी. एस. ओझा तथा क्षेत्रीय कृषि एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।कार्यक्रम में सीतापुर एवं आसपास के गांवों से आए 50 से अधिक गोपालक एवं कृषकों ने भाग लिया। गोष्ठी में गौ आधारित प्राकृतिक खेती, पंचगव्य उत्पादों के उपयोग, गोवंश संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया।अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त ने ग्राम स्तर पर आत्मनिर्भर गौशाला मॉडल, गोबर व गौमूत्र आधारित नवाचार और ग्राम पंचायतों में गौ आधारित रोजगार के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने किसानों और गोपालकों से अपील की कि गौ आधारित खेती भूमि की उर्वरता बढ़ाने के साथ–साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करती है।उन्होंने घोषणा की कि आयोग जल्द ही कुछ जिलों में पायलट आधार पर जैविक ग्राम की अवधारणा लागू करेगा,।

उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाने की तैयारी तेज की

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने वाराणसी में स्थित विश्वप्रसिद्ध बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ा दिया है। इस संबंध में आज लखनऊ के पर्यटन निदेशालय में पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी सितंबर माह में होने वाली यूनेस्को की बैठक के एजेंडे और प्रस्तावित कार्ययोजना पर गहन चर्चा हुई।उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सारनाथ हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया जाना न केवल भारत की वैश्विक विरासत को समृद्ध करेगा, बल्कि इससे पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक संरक्षण को भी बल मिलेगा। उन्होंने पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में किए गए प्रयासों के लिए बधाई दी। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तीन विश्व धरोहर स्थल कृ ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी कृ हैं, जो सभी आगरा में स्थित हैं। सारनाथ के सूची में शामिल होने से उत्तर प्रदेश पर्यटन के विश्व मानचित्र पर नए आयाम स्थापित करेगा, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात होगी।बैठक के बाद एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी मंत्री जयवीर सिंह से मिले और अब तक की प्रगति एवं आगे की रणनीति पर चर्चा की। भारत ने 2025–26 के नामांकन चक्र में सारनाथ को आधिकारिक रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया है।प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम और एएसआई के अधिकारियों ने सारनाथ के पारिस्थितिकी, सतत पर्यटन विकास और इको टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। वाराणसी में स्थानीय स्टेकहोल्डर्स और समुदाय के साथ एक बैठक आयोजित करने पर भी सहमति बनी।प्रमुख सचिव पर्यटन ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सारनाथ को कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकीसा, कुशीनगर और कौशांबी जैसे अन्य बौद्ध स्थलों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। वाराणसी और कुशीनगर एयरपोर्ट की व्यवस्था विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए की गई है। नेपाल से सटे होने के कारण भी बड़ी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु वाराणसी आते हैं।भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के महानिदेशक यदुवीर सिंह रावत और अतिरिक्त महानिदेशक जाह्नवीज शर्मा ने भी बैठक में अपनी टिप्पणियां दीं और आगे की रणनीति पर विचार–विमर्श किया।यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसी स्थल को शामिल करने के लिए वहां की मानव रचनात्मक प्रतिभा, प्रौद्योगिकी या वास्तुकला के विकास की कहानी, और मानव इतिहास के महत्वपूर्ण चरणों का प्रतिनिधित्व करने जैसे कई मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होता है। स्थल को पहले अस्थायी सूची में और बाद में स्थायी सूची में शामिल किया जाता है।इस महत्वपूर्ण बैठक में विशेष सचिव पर्यटन ईशा प्रिया, निदेशक पर्यटन (इको) प्रखर मिश्रा, लखनऊ एएसआई प्रभारी आफताब हुसैन सहित पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जिलों को लक्ष्य का आवंटन

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्राम्य विकास विभाग के संबंधित अधिकारियों को व्यापक दिशा–निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को झंडों के निर्माण के लिए आवंटित लक्ष्यों को युद्धस्तर पर पूरा करने के निर्देश दिये हैं।श्री मौर्य ने कहा कि 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत 2022 में शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अभियान राष्ट्रीय अस्मिता, देशभक्ति एवं गौरव का जन–भागीदारी आंदोलन बन चुका है।ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ झंडों का निर्माण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष 1.88 करोड़ से अधिक झंडों का उत्पादन सफलतापूर्वक किया गया था, जिसकी उच्च स्तर पर प्रशंसा हुई थी।कार्यक्रम के तहत झंडों का सम्मान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। स्वयं सहायता समूह इन झंडों का निर्माण कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराएंगे। लक्ष्य से अधिक झंडे स्थानीय प्रशासन और बाजारों में भी बेचे जा सकते हैं। समूहों की वित्तीय हानि न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।झंडों की बिक्री मिशन के अन्य घटकों से लाभान्वित व्यक्तियों के माध्यम से भी की जा सकती है। समूहों द्वारा निर्मित झंडों की सूचना नियमित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। झंडा फहराने के लिए समूह सदस्यों, मिशन के लाभार्थियों और नागरिकों को जागरूक किया जाएगा तथा उन्हें स्वयं सहायता समूहों से झंडा खरीदने के लिए प्रेरित किया जाएगा।कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ झंडों का निर्माण कराया जाएगा और इसका भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारियों को दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर उत्पादन की प्रगति का अनुश्रवण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लक्ष्य समय से पूरे हों।झंडों का निर्माण झंडा संहिता के अनुसार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। झंडा कोड ऑफ कंडक्ट का पालन अनिवार्य होगा। निर्मित झंडों की आपूर्ति सीधे ग्राम पंचायतों को की जाएगी तथा जरूरत पड़ने पर अन्य संस्थाओं को भी उपलब्ध कराई जाएगी। अतिरिक्त झंडों की आपूर्ति जरूरत के हिसाब से अन्य जिलों को भी की जा सकती है।सभी अधिकारियों को 31 अगस्त, 2025 तक भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करने और इसकी सूचना 5 सितंबर, 2025 तक मिशन मुख्यालय को देने का निर्देश दिया गया है। झंडों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और प्राप्ति रसीद ली जाएगी।इस वर्ष झंडा निर्माण के लिए अधिक निपुण स्वयं सहायता समूहों को कार्य आवंटित किया जाएगा। समूहों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए सघन अनुश्रवण और लगातार निगरानी की जाएगी।सभी संबंधित नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गए है

'विकसित उत्तर प्रदेश' की दिशा में राज्य स्तरीय परामर्श बैठक का आयोजन

लखनऊ, (संवाददाता)। 55वीं राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन, जो नवम्बर माह में प्रस्तावित है, की तैयारियों के क्रम में ईसीसीई (प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा), पोषण एवं माता–बाल देखभाल विषय पर 08 अगस्त 2025 को योजना भवन में एक राज्य स्तरीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती लीना जोहरी, सचिव श्रीमती बी. चंद्रकला और शिक्षा विभाग की महानिदेशक श्रीमती कंचन वर्मा उपस्थित रहीं।बैठक में प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक का उद्देश्य ईसीसीई, पोषण एवं माता–बाल देखभाल से जुड़े जमीनी अनुभव, सुझाव एवं नवाचार एकत्रित कर राष्ट्रीय मंच पर उत्तर प्रदेश की ओर से एक प्रभावी नीति निर्माण करना है।कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बच्चों के बौद्धिक विकास पर विशेष बल देते हुए कहा कि बच्चे ही भविष्य की पूंजी हैं और आज के निवेश से ही 'विकसित उत्तर प्रदेश' का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियमित तीन घंटे की निर्धारित ईसीसीई गतिविधि के तहत प्री–स्कूल किट के उपयोग पर जोर दिया।राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने आंगनवाड़ी केंद्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए पोषण और पढ़ाई दोनों का प्रशिक्षण 100 प्रतिशत शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव लीना जोहरी ने केंद्रों में पेयजल, शौचालय और विद्युत सुविधा सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया, ताकि बच्चे बेहतर शाला आधारित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें।बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं गैर–सरकारी संस्थाएं जैसे राकेट लर्निंग, यूनीसेफ, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। यूनीसेफ के शिक्षा विशेषज्ञ ऋत्विक पात्रा ने विकलांग बच्चों की पहचान और "खुशी की चौपाल" कार्यक्रम की नियमितता पर जोर दिया। राकेट लर्निंग की शुखना ने बताया कि उनकी संस्था ने बच्चों के कोगनेटिव विकास हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 'आधारशिला' गतिविधि विकसित करने में सहयोग दिया है, जो बच्चों के बौद्धिक विकास में सहायक होगी।आगामी पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए बाल्यावस्था में निवेश, आंगनवाड़ी केंद्रों का सशक्तिकरण तथा पोषण एवं देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है।

प्रदेश के सभी मदरसों में धूमधाम से मनाया जाएगा आजादी का महोत्सव

लखनऊ, (संवाददाता)। राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, दानिश आजाद अंसारी ने प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को पत्र भेजकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी मदरसों में आजादी का महोत्सव भव्य और व्यापक स्तर पर मनाने के निर्देश दिए हैं।श्री अंसारी ने कहा है कि 10 से 13 अगस्त तक सभी मदरसों में देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में स्वतंत्रता दिवस संगोष्ठी, छात्र–छात्राओं के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता शामिल होंगी, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों में देश के प्रति गर्व, सम्मान और जागरूकता की भावना को मजबूत करना है।उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी मदरसों में तिरंगा फहराया जाएगा और तिरंगा यात्रा का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, 15 अगस्त को हर वर्ष की तरह इस बार भी मदरसों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के साथ–साथ स्वच्छता जागरूकता अभियान और पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं, ताकि राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति का संदेश समाज में व्यापक रूप से फैल सके।राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य युवाओं और बच्चों में स्वतंत्रता संग्राम की गाथा, देशभक्तों के बलिदान और तिरंगे के महत्व के प्रति गहरी समझ और सम्मान विकसित करना है।

दस वारंटियो को कुमारगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

अयोध्या। कुमारगंज पुलिस ने सोमवार को विभिन्न मामलों में काफी दिनों से पुलिस की पकड़ से दूर रहे 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस संबंध में थानाध्यक्ष कुमारगंज ओमप्रकाश ने बताया एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर व एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी के निर्देश पर सीओ मिल्कीपुर के पर्यवेक्षण में यह अभियान चलाया जा रहा है।जिसके तहत उन्होंने यह कार्यवाही किया।बताया कि सोमवार को उन्होंने मेहदी हसन पुत्र

नक्कू उम्र करीब 35 वर्ष निवासी पूरे नेमा का पुरवा थाना कुमारगंज,शुकुरुल्लाह पुत्र करिया उम्र करीब 59 वर्ष निवासी पूरे नेमा का पुरवा थाना कुमारगंज,सिराज पुत्र मुमताज उम्र करीब 65 वर्ष निवासी पूरे नेमा का पुरवा थाना कुमारगंज,रज्जू पुत्र पीर मोहम्मद उम्र करीब 50 वर्ष निवासी पूरे नेमा का पुरवा थाना कुमारगंज,दुर्गा प्रसाद पुत्र रामरुप उम्र करीब 40 वर्ष निवासी पूरे नेमा का पुरवा थाना कुमारगंज,गुलसेर पुत्र मुमताज उम्र करीब 42 वर्ष निवासी पूरे नेमा का पुरवा थाना कुमारगंज,मो० सगीर पुत्र मुमताज उम्र करीब 50 वर्ष निवासी पूरे नेमा का पुरवा थाना कुमारगंज,मुख्तार उर्फ मोनू पुत्र स्व० मो० सरदार उम्र करीब 29 वर्ष निवासी पूरे नेमा का पुरवा थाना कुमारगंज,शहजाद पुत्र मुमताज उम्र करीब 62 वर्ष निवासी पूरे नेमा का पुरवा थाना कुमारगंज व रोजन पुत्र इस्लाम उम्र करीब 62 वर्ष निवासी पूरे नेमा का पुरवा थाना कुमारगंज को को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गिरफ्तार करने वाली टीम में उनके अलावा उ०नि० उ०नि० नीरज चौरसिया थाना कुमारगंज सहित अन्य पुलिस कर्मी शामिल रहे।

पति द्वारा पत्नी की गला रेतकर हत्या

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना)

पति द्वारा पत्नी की गला काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह बेटी ने मां का शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने जरूरी नमूने जुटाए हैं। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के बेहटा गोकुल गांव में ही रीत कुमार परिवार के साथ रहता था। पुलिस ने बताया कि वह खुरपी, बांका , करछुली आदि बनाने का काम करता था। बेटी रंजना के अनुसार रीत कुमार और उसकी पत्नी रीता के बीच पिछले कुछ दिनों से अलग–अलग बातों को लेकर विवाद हो रहा था। रविवार रात रीता घर में सोई हुई थी ।रात में किसी समय रीत कुमार ने धारदार हथियार से गला रेत कर रीता की हत्या कर दी और भाग गया। सोमवार सुबह रंजना जागी तो उसने मां का शव पड़ा देखा और पिता मौके से गायब था। इसकी जानकारी उसने पुलिस को दी। कुछ ही देर में ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर लग गई ।प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घरेलू कलह में हत्या की गई है ।मृतक की बड़ी पुत्री रंजना की तहरीर पर पति रीत कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

चावला राइडर्स प्राइवेट लिमिटेड देवकाली मे हंटर नए ग्रेनाइट आकर्षण रंग में हुआ लॉन्च

अयोध्या। सोमवार को कोतवाली नगर क्षेत्र के चावला राइडर्स प्राइवेट लिमिटेड देवकाली मे हंटर नए ग्रेनाइट आकर्षण रंग में लॉन्च किया गया।इस मौके पर पत्रकार राजेश श्रीवास्तव तथा डॉक्टर अजय तिवारी ने संयुक्त रूप से केक काटकर इसका शुभारंभ किया।इस मौके पर कंपनी के डायरेक्टर पिंकेश चावला ने बताया कि इसमें अत्याधुनिक तकनीक से लैस और ग्राहकों की मांग पर असिस्ट स्लिप क्लच,नेविगेशन,रियल शाकर,

ग्राउंड क्लियरेंस, हन्डल बार, मोबाइल चार्ज करने के लिए फास्ट टी टाइप चार्जर, के साथ–साथ सेट में भी काफी बदलाव किया गया है।इस मौके पर मार्केटिंग मैनेजर हरप्रीत ने बताया कि सीट के नए अपडेट से बाइक सवारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी और दूर तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा ही नहीं पूरे विश्वास है कि ग्राहकों को यह हंटर जरूर ही पसंद आएगी। इस मौके पर सर्विस मैनेजर मोहम्मद शोएब के अलावा पंडित ऋषि प्रसाद के साथ–साथ अन्य कर्मचारी व ग्राहक मौजूद रहे।

राखी बंधवाने मां के साथ मामा के घर गए युवक ने रेलवे पुल से गोमती नदी में लगाई छलांग मौत ,आज शव बरामद

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। गौराबादशाहपुर थाना अंतर्गत शनिवार मामा के घर राखी बंधवाने गये युवक ने रेलवे पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजनो ने पुलिस पर सूचना देने के बाद भी उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। थाना क्षेत्र के सरसौडा गांव निवासी महेश (25)पुत्र हरी लाल कन्नौजिया अपनी मां को लेकर 9 अगस्त को राखी बंधवाने अपने मामा के घर गया था। रात लगभग 8 बजे जब मामा के घर वाले उसे भोजन के लिए खोजने लगे तो वह नहीं मिला। आसपास तलाश करने के बाद अनहोनी की आशंका से वह निकट स्थित बशीरपुर रेलवे पुल पर पहुंचे तो आसपास के लोगों ने बताया कि लगभग 8 बजे किसी ने यहां से नदी में छलांग लगाई है। घर वालों ने अनहोनी की आशंका से तुरंत जफराबाद थाने में तहरीर देकर गायब युवक को खोजने की गुहार लगाई। परंतु पुलिस ने उदासीन रवैया अपना लिया था। थक हार कर सोमवार को सुबह घर वालों ने अपने संसाधन से नाव किराए पर लेकर बशीरपुर से रामघाट तक तलाशी अभियान चलाया। निजी गोताखोरों ने रामघाट के पास तलहटी में पड़े महेश का शव बरामद कर लिया।इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच कर मामले की छानबीन में जुटी है। इस मामले पर पूछे जाने पर चौकी प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि मौके पर सिपाही भेजे गये थे गोमती नदी में भी तलाशी की गई थी पर शव का पता नही चला था।

स्वदेशी जागरण मंच,सम विचार संगठनों, संस्थाओं ने विदेशी सामानों को लेकर फूंका ट्रंप का पुतला

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना) विदेशी वस्तुओं को अमेरिका अपनी नीतियों से बंधुआ बनाकर, विदेशी वस्तुओं को देश में नहीं बिकने देंगे ,अब ये नया भारत है गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। प्रतिबंध लगाकर अमेरिका चाहता है कि वह भारत में व्यापार कर ले,कतई नहीं होने देंगे। जन जागरण अभियान चलाकर कंपनियों और विदेशी वस्तुओं के सामान का बहिष्कार करके बंद कराया जाएगाष उक्त विचार सिनेमा चौराहा स्थित सोल्जर बोर्ड चौराहा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन व विदेशी सामानों का दहन करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत समन्वयक हर्षवर्धन सिंह ने व्यक्त किए। स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में सम विचार संगठनों,स्वयं सेवी संस्थाओं ने सोल्जर बोर्ड चौराहा पर एकत्र होकर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के विरोध में विदेशी सामानों का बहिष्कार करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका, साथ ही विदेशी सामानों की होली जलाई ।इस अवसर पर प्रांत समन्वयक हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि अब अमेरिका व अन्य देशों की दादागिरी हर भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा ।अपनी नीतियों में बांधकर अपनी नीति के अनुसार व्यापार नहीं कर सकेंगे, अब पहले वाला भारत नहीं जो धमकियों से डर जाएगा। जिला संयोजक अवनीश द्विवेदी ने कहा कि आगे जन जागरण करके विदेशी सामानों और स्वदेशी सामानों की सूची सभी को वितरित की जाएगी और स्वदेशी सामानों के उपयोग करने की अपील की जाएगी। नगर संयोजक शिव सेवक गुप्ता ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच अपनी अग्रिम योजनाओं में जन जागरण कर जनपद में स्थापित अमेरिकी और विदेशी कंपनियों के सामानों का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी अपनाने की अपील करेगी और इन कंपनियों को जनपद में व्यापार बंद करने के लिए विवश किया जाएगा। इसके लिए सभी व्यापारिक संगठनों से वार्ता कर ली गई है। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा श्री कृष्ण शास्त्री , हरदोई पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार अग्निहोत्री,सेवा भारती के सुधीर अवस्थी,भाजपा जिला अध्यक्ष महिला सभा अलका गुप्ता,मधुबाला गुप्ता,पतंजलि योग समिति प्रभारी विनीता पांडे, बहादुर बेटियां फाउंडेशन की संस्थापिका कुसुम लता गुप्ता,महिला मोर्चा,पम्मी त्रिपाठी संरक्षक महिला विंग स्वदेशी जागरण मंच,सुशील द्विवेदी विहिप,अशोक सिंह आजाद गौ सेवा गतिविधि, डॉ पुष्पेंद्र शुक्ला,रामकृपाल सिंह,आशुतोष बाजपेई आजाद,जितेंद्र सिंह,आदि विभिन्न सामाजिक संगठनों और सम विचार संगठनों के पदाधिकारी और देश प्रेमी जन उपस्थित रहे।

जेठपुरा में कक्षा 1 से 5 तक चल रहे बिना मान्यता के विद्यालय सील

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर जिला बेसिक शिक्षा अधि ाकारी डॉ0 गोरखनाथ पटेल के निर्देशन में खंड शिक्षा अधिकारी करंजाकला श्रवण कुमार यादव ने सोमवार को न्याय पंचायत मल्हनी के ग्राम पंचायत जेठपुरा में कक्षा 1 से 5 तक चल रहे बिना मान्यता के विद्यालय को सील कर दिया। इस अवैध संस्थान में करीब 200 बच्चे अध्ययनरत थे। खंड शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी कर कक्षाओं का संचालन रोकने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इन मासूम बच्चों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ भी है। खंड शिक्षा अधिकारी ने चेतावनी भी दी कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा विभाग की मान्यता शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील किया कि अपने बच्चों को केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही दाखिला दिलाएं, ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके।

कचरा गिराने गईं 20 गाड़ियों को ग्रामीणों ने रोका

गोरखपुर, (संवाददाता)। जंगल कौड़िया ब्लॉक के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर और जमुआड़ में फ्रेश वेस्ट बायो ट्रामल प्लांट पर रविवार को कचरा गिराने गई नगर निगम की गाड़ी को ग्रामीणों ने रोक दिया।

करीब 20 गाड़ियां कचरा लेकर खड़ी रहीं।मौके पर पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों ने धरना–प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब तीन घंटे बाद पहुंचे अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने आश्वस्त किया कि अब यहां कचरा नहीं गिराया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने ६ ारना–प्रदर्शन खत्म किया।

जानकारी के मुताबिक, रविवार की सुबह नौ बजे शहर से कचरा लेकर नगर निगम की गाड़ियां जंगल कौड़िया फोरलेन के समीप नगर निगम से संचालित फ्रेश वेस्ट बायो ट्रामल प्लांट पर पहुंची। इस बीच ग्रामीण भी पहुंच गए। उन्होंने प्लांट पर कचरा गिराने और उसके निस्तारण का विरोध शुरू कर दिया।ग्रामीणों ने कालेसर–जमुआड़ फोरलेन मार्ग पर नगर निगम की 20 कचरा गाड़ियों को रोक दिया और प्लांट के सामने धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना था कि करीब 10–11 माह से जमुआड़ गांव के पास खुले में कचरा डंप किया जा रहा है। इससे पूरे इलाके में दुर्गंध फैल रही है।कचरा में मृत जानवर, मेडिकल वेस्ट तक शामिल होता है। इसकी वजह से बच्चों का खेलना–कूदना बंद हो गया है। लोग सुबह टहलने नहीं निकल पा रहे हैं। गांव में मक्खियां काफी ज्यादा हो गई हैं। आए दिन संक्रामक बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। करीब तीन घंटे के प्रदर्शन के बाद अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह धरना स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि अब उस स्थान पर कूड़ा नहीं गिराया जाएगा। अपर नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने ६ ारना–प्रदर्शन समाप्त किया। इस दौरान जमुआड़ के ग्राम प्रधान ऋतुराज सागर, मोहम्मदपुर के ग्राम प्रधान अभिमन्यु यादव, सोहन निषाद, रामऔतार निषाद, ज्ञान यादव, गब्बू यादव, शिवा यादव, जीतेंद्र निषाद आदि मौजूद रहे।

थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार भी नहीं मना सके चिलुआताल थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव और नायब तहसीलदार अरविंद कुमार पांडेय ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के काफी समझाने के बावजूद ग्रामीणों ने धरना समाप्त करने से इन्कार कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक नगर आयुक्त आकर आश्वासन नहीं देंगे, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इसी बीच अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह पहुंचे और उन्होंने आश्वस्त किया यहां का सारा कचरा निस्तारित कराएंगे। तत्काल प्रभाव से यहां कूड़ा गिराया जाना बंद कराया जाएगा। जैविक कचरे से दुर्गंध आती हैं उन्हें बॉयोडीकंपोजर या अन्य विधियों का उपयोग कर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही कूड़ा निस्तारण केंद्र दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा।

सावन खत्म...'रोहू' के लिए कोहराम, हाईवे भी कर दिया जाम

गोरखपुर, (संवाददाता)। सावन खत्म होने के साथ ही शौकीन नॉनवेज के लिए दुकानों पर टूट पड़े। पीपीगंज में शनिवार शाम रोहू मछली खरीदने के लिए दो ग्राहकों के बीच मारपीट हो गई। हंगामा देखने के लिए हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने दोनों को समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानने पर उन्हें हिरासत में ले लिया। दोनों का शांतिभंग में चालान कर दिया गया।घटना से संबंधित वीडियो रविवार को वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक, पीपीगंज कस्बे में नेपाल जाने वाले रास्ते पर मछली की दुकान है। शनिवार शाम 6रू30 बजे कोल्हुआ का मुकेश कुमार चौहान बाइक से मछली खरीदने पहुंचा। थोड़ी ही देर बाद वहां पर भगवानपुर का रहने वाला रितिक चौहान भी आ गया। दोनों ने पांच किलो मछली का ऑर्डर दिया। दुकानदार के पास रोहू मछली चार किलो ही बची थी। दोनों का कहना था कि पहले उसने मछली पसंद की है। इसलिए उसे ही मिलनी चाहिए। दुकानदार के सामने दोनों के बीच काफी देर तक तू–तू, मैं–मैं होती रही। दुकानदार ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वे उसकी बात नहीं माने। इसी बीच दोनों ने कॉल करके अपने साथियों को बुला लिया। थोड़ी ही देर बाद दो बाइक से पांच युवक और आ गए। एक पक्ष के युवकों ने मछली खरीदने आए दूसरे पक्ष के युवक को धक्का देकर गिरा दिया। उसकी शर्ट फाड़ दी। इसके बाद दूसरे पक्ष के युवकों ने भी हमला कर दिया। आधे घंटे तक बीच रोड पर हंगामा होता रहा। कुछ राहगीर इसका वीडियो बनाने लगे। हंगामे से नेपाल जाने वाले नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। लोग गाड़ी खड़ी करके तमाशा देखने लगे।

वीर शहीदी के सम्मान में डीएम के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस पूर्व निकली भव्य तिरंगा यात्रा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,।ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे प्रदेश में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में सोमवार सुबह कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधि ाकारी डॉ. दिनेश चंद्र के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में जिला प्रशासन के अधिकारी–कर्मचारी, मदरसों के छात्र–छात्राएं, दिव्यांग बच्चे, विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं तिरंगा हाथ में लेकर शामिल हुईं। कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ हुई यात्रा लाइन बाजार चौराहे से होते हुए सबसे पहले गांध ाी तिराहे पहुँची, जहां जिलाधिकारी सहित अधिकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ते हुए अंबेडकर तिराहे पहुँची, जहां डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन किया गया। इस अवसर पर डीएम डॉ. दिनेश चंद्र ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस पूर्व सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जौनपुर, जिसे शिराज–ए–हिंद के नाम से जाना जाता है, में लोगों का जोश और जनसैलाब अद्वितीय है। विशेष रूप से अल्पसंख्यक विभाग के स्कूलों के बच्चों की सहभागिता सराहनीय रही।" उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घर पर तिरंगा अवश्य लगाएं। दिव्यांग प्रतिभागियों के उत्साह की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, "दिव्यांग व्यक्ति शारीरिक रूप से सीमित हो सकते हैं, लेकिन उनकी मानसिक प्रेरणा और सहभागिता में कहीं भी दिव्यांगता का असर नजर नहीं आता।" इस दौरान तिरंगा यात्रा में सभी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे।

पीयू में हर घर तिरंगा के अंतर्गत निकाली गई बाइक याता

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में ष्हर घर तिरंगा अभियान 2025ष के तहत सोमवार को तिरंगा बाइक यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। यह यात्रा विश्वविद्यालय परिसर स्थित सरस्वती सदन, कुलपति कार्यालय से अपराह्न 12रू00 बजे कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगे से सजी बाइकों पर सवार छात्र–छात्राओं के जोश और उमंग ने परिसर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। यात्रा विश्वविद्यालय परिसर से निकलकर आस–पास के गोद लिए गए जासोपुर, कुकड़ीपुर गांव में पहुंची। जहां ग्रामीणों ने भी इस पहल का स्वागत किया। इस दौरान ष्भारत माता की जयष और ष्वंदे मातरम्ष के गगनभेदी नारे वातावरण में गूंजते रहे। कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने उद्बोधन में कहा कि यह यात्रा न केवल राष्ट्रध्वज के सम्मान का प्रतीक है, बल्कि युवाओं में देशभक्ति और एकता के संदेश को जन–जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के उत्साह और समर्पण की सराहना की। इस अवसर पर छात्र अधिष्ठाता प्रो. प्रमोद यादव, प्रो. राकेश यादव, प्रो. राजबहादुर यादव, डॉ. अनुराग मिश्र ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में नोडल डॉ. शशिकांत यादव, डॉ. सुनील कुमार, डॉ दिग्विजय सिंह राठौर, डॉ वनिता सिंह, डॉ. प्रियंका, डॉ राहुल राय, बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं शामिल हुए। यात्रा का समापन विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रगान के साथ हुआ।

राजन इण्टर नेशनल एकेडमी में उल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व

बस्ती , (संवाददाता)। राजन इण्टर नेशनल एकेडमी में भाई बहन के प्रेम को समर्पित रक्षा बंधन का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। छात्राओं ने प्रबन्ध निदेशिका शिखा चतुर्वेदी के निर्देशन और कार्यकारी निदेशक संजीव पाण्डेय के संयोजन में प्रधानाचार्य सानू एन्टोनी, शिक्षकों और छात्रों को रक्षा बंधन बांध ाा।कार्यकारी निदेशक संजीव पाण्डेय ने छात्रों को रक्षाा बंधन पर्व की विशेषता बताया। कहा कि यह पर्व भाई –बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। भारतीय परम्पराओं का यह एक ऐसा पर्व है, जो केवल भाई बहन के स्नेह के साथ साथ हर सामाजिक सम्बन्ध को मजबूत करता है इस लिये यह पर्व भाई–बहन को आपस में जोडने के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व भी रखता है। उन्होने छात्रों से कहा कि इस रक्षा बंधन को सामान्य धागा समझने की भूल मत करना। यह परस्पर प्रेम, त्याग और समय आने पर बहन की रक्षा के लिये सर्वस्व न्यौछावर करने का पर्व है।प्रधानाचार्य सानू एन्टोनी ने छात्रों को रक्षाबंधन पर्व

की शुभकामना दिया। कहा कि रक्षा बंधन का पर्व विशेष रुप से भावनाओं और संवेदनाओं का पर्व है. एक ऐसा बंधन जो दो जनों को स्नेह की धागे से बांध ले। रक्षा बंधन को भाई – बहन तक ही सीमित रखना सही नहीं होगा. बल्कि ऐसा कोई भी बंधन जो किसी को भी बांध सकता है। प्ले वे से प्री प्राइमरी तक के छात्र–छात्राओं ने रक्षाबंधन की खुशियों को साझा किया। कार्यक्रम में रेखा श्रीवास्तव, प्रमिला शुक्ला, शिक्षा बरनवाल, प्रभा त्रिपाठी, नीलम श्रीवास्तवा, निशु उपाध्याय, अर्चना पटेल, श्वेता त्रिपाठी, अर्चना द्विवेदी, सुमन दुबे, आकृति पांडे, पूनम, शालिनी, संगीता, जेरीन, मनीषा गुप्ता, अभिषेक पटेल, माया सिंह, माया शुक्ला, श्रद्धा, आकृति साहू, वेदिका, सिमरन, देविका, सुष्मिता मन्ना, संजय, नलिन, अमित मिश्रा, मनीषा गुप्ता, शिवांश उपाध्याय, सौरभ पाण्डेय, जीत यदुवंश, मनीष मिश्रा, रामस्वरूप यादव अखिलेश, मोहम्मद अजीम, अरुण बहादुर श्रीवास्तव, राम निरंजन गुप्ता के साथ ही सैकड़ो छात्रों ने हिस्सा लिया।

स्कूली छाताओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन

बस्ती , (संवाददाता)। गजाधर सिंह अंगद सिंह एकेडमी हर्रैया के परिसर में भाई–बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षा बंधन का पर्व धूमधाम से शुक्रवार को मनाया गया। स्कूली छात्राओं ने थाना प्रभारी हर्रैया तहसीलदार सिंह, पुलिस कर्मियों, प्रधानाचार्य, शिक्षकों और छात्रों को रक्षाबंधन बांधा। थाना प्रभारी ने कहा कि यह पर्व भाई –बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। भारतीय परम्पराओं का यह एक ऐसा पर्व है, जो भाई बहन के स्नेह के साथ–साथ हर सामाजिक सम्बन्ध ा को मजबूत करता है इस लिये यह पर्व भाई–बहन को आपस में जोड़ने के साथ–साथ सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व भी रखता है। उन्होंने कहा कि इस रक्षाबंधन को सामान्य धागा समझने की भूल मत करना, यह परस्पर प्रेम, त्याग और समय आने पर बहन की रक्षा के लिये सर्वस्व न्यौछावर करने का पर्व है। उन्होंने बताया कि द्रौपदी ने श्रीकृष्ण को धागा बांधा था और जब वह विपत्ति में फंसी तो उन्हें अपने भाई कान्हा की याद आई और कान्हा इतनी तीव्र गति से उनकी रक्षा के लिए बढ़े कि उनके वाहन गरुड़ भी उनसे पीछे रह गये। यह देखकर किसी कवि ने लिखा है ।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक
देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।